	Per Capita NNP		Per Capita GNP	
	1980-81 Prices	Current Prices	1980-81 Prices	Current Prices
1992-93* . . .	2216	6249	2495	7070
1993-94@ . .	2255	NA	2544	NA

*Quick Estimates @Advance Estimates NA : Not Available, NNP : Net National Product, GNP : Gross National Product.

Goswami Panel Report in Industrial Sickness and Corporate Restructure

3765. SHRI SURESH PACHOURI : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether Government have examined the Goswami Panel Report on industrial sickness and corporate restructuring ;

(b) if so, the recommendations which have so far been examined by Government ; and

(c) the total number of suggestions incorporated and by when these are likely to be implemented ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI M. V. CHANDRASHEKHAR MURTHY) : (a) to (c) The recommendations of the Goswami Committee Report on Industrial Sickness and corporate restructuring are under consideration of the Government.

निजीकरण और उदारीकरण की नई आर्थिक नीति

3766. श्री अनंत राव जायसवाल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निजीकरण और उदारीकरण की नई आर्थिक नीति के बारे में किसी पैकेज को अन्तिम रूप दिया है ;

(ख) पैकेज में शामिल कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) पैकेज में शामिल उन कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है जिन्हें लागू कर दिया गया है और प्रत्येक को कब से लागू किया गया है ; और

(घ) पैकेज में शामिल बकाया उन कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है जिन्हें लागू किया जाना है और प्रत्येक को कब से लागू किये जाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चंद्रशेखर मूर्ती) : (क) से (घ) जुलाई, 1991 में सरकार द्वारा घोषित नई औद्योगिक नीति ने औद्योगिक क्षेत्र में उदारीकरण हेतु एक ढांचा मुहैया कराया । इस समय, केवल 15 मदों को छोड़कर औद्योगिक लाइसेंस प्रणाली को सभी मदों से हटा दिया गया है ; सरकारी क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों की संख्या को कम करके 6 कर दिया गया है ; और सरकारी क्षेत्र के निवेश हेतु निर्धारित आधार-ढांचे संबंधी कुछ चुनिन्दा क्षेत्रों में निजी क्षेत्र की भागीदारी की भी अनुमति दी गई है । विदेशी निजी निवेश संबंधी नीति को काफी उदार बनाया गया है जिसमें अनेक उद्योगों में 51 प्रतिशत इक्विटी तक विदेशी निवेश हेतु स्वतः अनुमोदन के उपबन्ध तथा मापदंडों और प्रक्रियाओं में छूट देना शामिल है ।

सरकार ने अब सरकारी क्षेत्र में अनेक सुधार आरंभ किए हैं । इन सुधारों में अन्य बातों के अलावा ये शामिल हैं : सरकारी क्षेत्र के घाटे में चल रहे उद्यमों को बायोजना—भिन्न ऋणों के रूप में दी जा रही बंजटीय सहायता को चरणों में समाप्त करना, बजट हेतु गैरस्फीतिकारी संसाधन जुटाने के लिए, तथा सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के प्रबन्ध में स्वामित्व का आधार व्यापक करने और अधिक वाणिज्यिक दिशा देने के लिए सरकारी क्षेत्र के चुनिन्दा उद्यमों में 49 प्रतिशत तक का विनिवेश करना, सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को विदेशों में संयुक्त उद्यम लगाने तथा बाजार से नई इक्विटी जुटाने की अनुमति देना तथा सरकारी क्षेत्र के रुग्ण उद्यमों को रुग्ण औद्योगिक कंपनी अधिनियम (एस० आई० सी० ए०) के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत लाना ।

Lending Facilities to Farmers in Punjab

3767. SHRI IQBAL SINGH : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that lending facilities from financial institutes and banks to the farmers and other people of Punjab are very low ;

(b) if so, the details thereof and the reasons therefor ; and

(c) what steps Government propose to take to increase lending facilities from the said financial institutions to farmers of the State ?